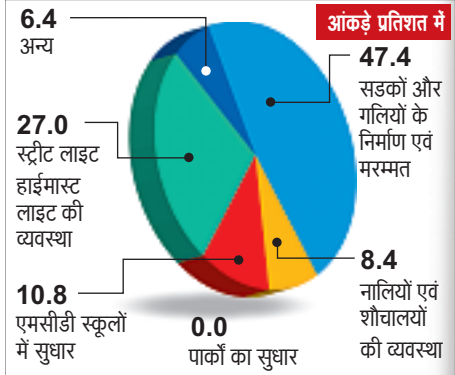


दिव्य जायसवाल (भाजपा)
 वार्ड नंबर 247 (रामनगर)
 शैक्षिक योग्यता बीए
 आपराधिक मामले कोई नहीं

जनता के लिए जरूरी सभी विकास कार्यों पर ध्यान दिया गया है। एक-एक गली और रास्ते का निरीक्षण करके कार्य करवा रहा हूँ

नगर निगम में प्रदर्शन (अप्रैल 2007-मार्च 2009)
 निगम की बैठकों में उपस्थिति 52/56
 सवाल पूछे कोई नहीं

उपलब्ध फंड का ब्यौरा (अप्रैल 07-मार्च 09)
 कुल उपलब्ध राशि 2.71 करोड़ रु
 आवंटित राशि 2.70 करोड़ रु



* प्रत्येक पार्क को 2007-08 में 71 लाख तथा 2008-09 में 2 करोड़ वार्ड में विकास कार्य के लिए मिले

समितियों में प्रदर्शन (अप्रैल 2007 से मार्च 2009)

समिति	पद	अवधि	उपस्थिति
वार्ड समिति (शहादरा उत्तरी)	सदस्य	2007-09	11/65
स्लम एवं जेजे	उपाध्यक्ष	2007-09	10/16
आवासन	अध्यक्ष	2007-09	3/4
पर्यावरण प्रबंधन	अध्यक्ष	2007-08	6/6
हिन्दी	अध्यक्ष	2007-09	3/3
खेल-कूद प्रोत्साहन	अध्यक्ष	2007-09	3/3
मलेरिया निरोधक	अध्यक्ष	2007-09	6/6
लाभकारी परियोजना	उपाध्यक्ष	2007-09	5/9
बाढ़ नियंत्रण	उपाध्यक्ष	2007-09	1/2
गलियों का नामकरण	उपाध्यक्ष	2007-09	5/9
राष्ट्रीय त्योहार	उपाध्यक्ष	2008-09	1/1
मांट एन एड	उपाध्यक्ष	2008-09	उपलब्ध नहीं

विकास कार्य नहीं हुआ, इसी कारण वर्तमान पार्क विधायकी का चुनाव हार गए। क्षेत्र में सफाई और रास्तों की हालत दयनीय है

सुभाष जैन, कांग्रेस, हारे हुए उम्मीदवार

सड़कें तंग हैं, चौड़ीकरण की जरूरत है

पार्क जी का रिपोर्ट कार्ड हिन्दुस्तान सतर्क नागरिक संगठन

वार्ड नंबर 247 (रामनगर)

राम नगर वार्ड क्षेत्र के रास्तों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। लोनी रोड को चौड़ा करने की दरकार सबसे ज्यादा है। इसके लिए योजना भी बनाई जा रही है। दिक्कत को दूर करने के लिए क्षेत्र में पड़ने वाली जोटी रोड का हिस्सा चौड़ा



दिव्य जायसवाल ने स्कूल बनाया। • सर्वश

किया गया। रोहतास नगर ईस्ट में स्थित विद्यालय की हालत दुरुस्त करने के लिए भी कार्य किया गया है। वार्ड में सड़कों की कमी नहीं है। विभिन्न रास्तों पर बरसात के दिनों में जल भराव होता है, इस कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशान होना पड़ता है। क्षेत्र में सफाई की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जगह-जगह गंदगी फैली रहती है। ऐसी स्थिति में लोगों को दुर्गंध का भी शिकार होना पड़ता है। पार्क फंड से सड़कों-गलियों की मरम्मत और निर्माण पर सवा करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। लेकिन, पार्कों के लिए एक भी रुपया आवंटित नहीं किया गया। पथ प्रकाश की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सत्तर लाख रुपए से ज्यादा की राशि आवंटित की गई है, लेकिन कई क्षेत्रों में काम किया जाना बाकी है।

विकास को तरस रहे हैं अवैध कॉलोनियों के लोग

वार्ड नंबर 263 (सबोली)

सबोली वार्ड में कई अवैध कॉलोनियां हैं, जिनकी हालत अत्यंत दयनीय है। पार्क फंड का कहना है कि इन कॉलोनियों में फंड का पैसा लगाने की हट्ट नहीं है। इस कारण विकास कार्य नहीं करवाए जा सकते। सरकार ने इस क्षेत्र के लोगों को मताधिकार तो दे दिया है, लेकिन इस क्षेत्र में विकास कार्य करने पर पावंदी लगी है। ऐसे में जनता को जवाब देते नहीं बनता। क्षेत्र में सामुदायिक भवन और बारात घर की जरूरत है। लेकिन, स्थान की उपलब्धता नहीं होने के कारण इस समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है। क्षेत्र में जल भराव बहुत होता है, इस कारण सौ से ज्यादा पुलियों का निर्माण भी करवाया गया है। कुछ सड़कों को कंक्रीट से बनाया गया है, ताकि वह जल्दी-जल्दी खराब नहीं हों। क्षेत्र में वृद्ध व्यक्तियों के लिए मनोरंजन केन्द्र और युवाओं के लिए व्यायाम केन्द्र बनाने का कार्य किया जाना है। इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। कम्प्यूटि सेंटर बनाने के लिए भी कोशिश की जा रही है।

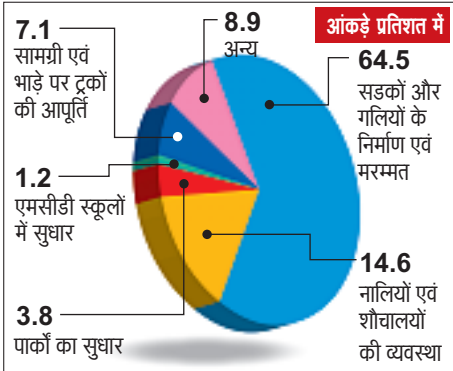
समारोह के लिए नहीं मिलता कोई ठिकाना

वार्ड नंबर 251 (न्यू उस्मानपुर)

न्यू उस्मानपुर वार्ड में सामुदायिक भवन की दरकार है। इसके अभाव में क्षेत्र के लोगों को सामाजिक समारोहों का आयोजन करने के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है। सड़कों और गलियों के निर्माण-मरम्मत पर डेढ़ करोड़ रु. से ज्यादा राशि पार्क फंड से आवंटित की गई है। बावजूद कई क्षेत्रों में सड़कों को दुरुस्त करने के लिए कार्य किया जाना है। पानी की टंकी, गौतमपुरी के सामने की रोड की हालत ठीक नहीं है।

रास्ता खराब होने के कारण स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत होती है। पार्कों पर पार्क फंड का बहुत पैसा खर्च नहीं किया गया है, जो कार्य करवाए गए हैं, वह नाकाफ़ी हैं। पार्कों की स्थिति कुछ स्थानों को छोड़कर बाकी जगह ज्यादा अच्छी नहीं है। कुछ जगहों पर पार्क की स्थिति सुधारने के लिए विकास कार्य किया जा रहा है। एक प्राथमिक विद्यालय को दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है। क्षेत्र में पथ प्रकाश की व्यवस्था कहीं पर दुरुस्त है तो कहीं पर लाइट जलती ही नहीं है और अंधेरा रहता है।

उपलब्ध फंड का ब्यौरा (अप्रैल 07-मार्च 09)



* प्रत्येक पार्क को 2007-08 में 71 लाख तथा 2008-09 में 2 करोड़ वार्ड में विकास कार्य के लिए मिले

जनता में निराशा है, निगम के कार्य होते नहीं और दूसरे सरकारी विकास कार्यों में रोड़ा अलग अटकाया जाता है

ब्रह्मस्वरूप शर्मा, कांग्रेस, हारे हुए उम्मीदवार

क्षेत्र में सफाई की हालत खस्ता है। किसी भी सड़क पर ठीक से काम नहीं किया गया है, जनता बुरी तरह से परेशान है। कमलेश मिश्रा, कांग्रेस, हारे हुए पार्क

* वह रिपोर्ट कार्ड सतर्क नागरिक संगठन (सोसाइटी फॉर सिटीजंस चिंताओं का इन्शिएटिव) के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी पर आधारित है।

व्यापारी को फंसाने वाले इंस्पेक्टर और एसआई फंसे

अब तक कार्रवाई न होने पर अदालत ने दिया आवमानना कार्रवाई का आदेश

कार्यालय संवाददाता
नई दिल्ली

साऊथ एक्स में रेहड़ी वालों से पुलिस की अवैध वसूली का भंडाफोड़ करने वाले एक व्यापारी को फर्जी मामले में फंसाने वाले एक इंस्पेक्टर और दो एसएचओ के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशानुसार आवमानना कार्रवाई का संकट गहरा गया है।

न्यायाधीश एस एन धींगरा ने तीनों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के उपराज्यापाल के आदेश का अब तक पालन न होने पर अपने रजिस्ट्रार जनरल को निचली अदालत में इनके खिलाफ आवमानना कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। स्थानीय व्यापारी मजीत सिंह चुग की याचिका पर अदालत ने रजिस्ट्रार जनरल को यह आदेश दिया है।

इस मामले में चुग और उसके पूर्व सैन्य अधिकारी पिता के खिलाफ हत्या के प्रयास का गलत मामला दर्ज किया गया था।

हाईकोर्ट में यह साबित होने के बाद उपराज्यापाल ने गत जनवरी में इंस्पेक्टर अशोक कुमार, एसआई संदीप शर्मा

फर्जीवाड़ा

साऊथ एक्स में रेहड़ी वालों से पुलिस की अवैध वसूली का भंडाफोड़ करने वाले एक व्यापारी को फर्जी मामले में फंसाने का मामला

और सुनील जैन के खिलाफ कार्रवाई करने का पुलिस आयुक्त को आदेश दिया था।

इस पर कोई कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को निचली अदालत में इन तीनों के खिलाफ फर्जी मामला दर्ज करने की शिकायत दर्ज कराते हुए आवमानना कार्रवाई भी शुरू करने का आदेश दिया। इस मामले में मंजीत सिंह चुग और पिता मोहिंदर चुग को निचली अदालत ने 2004 में इन्हें दोषी भी ठहरा दिया लेकिन हाईकोर्ट से दोनों को 2008 में बरी कर दिया गया। मामले की तहकीकात में पता चला कि पुलिस ने गलत सबूतों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया था और बाद में अपनी गलती को स्वीकार भी किया।

मामले में दिलचस्प बात यह है कि इनके खिलाफ जिस व्यक्ति की गैरइरादतन हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया उसे चुग ने साऊथ एक्स स्थित अपनी ही दुकान में चोरी करते पकड़ कर पुलिस को सौंपा था।

पहचान की अपील

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अज्ञात व्यक्ति का शव जिसकी उम्र : लगभग 30-35 साल, कद : 5'10", रंग : सौंवाला, शरीर : मध्यम, चेहरा : गोल, पीले रंग की टी-शर्ट और स्टील ग्रेग की पैट व अपडरवियर पहने हुए बाहरी रिंग रोड नजदीक आईटीआई धीरपुर, दिल्ली में घायल अवस्था में पाया गया। उसे ट्रॉमा सेंटर लाया गया जहां 21.02.2009 को उसकी मृत्यु हुई। इस संदर्भ में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 33/09 दिनांक 21.02.2009 थाना तिमारपुर, दिल्ली में दर्ज है।

यदि किसी भी व्यक्ति को इस मृतक के बारे में कोई जानकारी या सुराग मिले तो अधोहस्ताक्षरी को निम्नलिखित पते या फोन नंबरों पर सूचित करने की कृपा करें।
 थानाध्यक्ष, थाना तिमारपुर, दिल्ली
 दूरभाष सं. 23812734, 23814421

DP/429/N/09

सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी द्वारा मोबाइल टॉवरों के लाइसेंस शुल्क में वृद्धि पर अंतरिम रोक लगाने की पर रोक लगाने से इंकार किया

प्रमुख संवाददाता
नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा मोबाइल फोन टावरों के लिए लाइसेंस शुल्क में वृद्धि किए जाने पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन एमसीडी से कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के एक निर्देश के अनुसार मोबाइल आपरेटरों द्वारा जमा एफडीआर को न भुनाएं।

मोबाइल परिचालकों के अंतरिम रोक संबंधी अनुरोध को अस्वीकार करते हुए न्यायालय ने कहा कि इस मौके पर मामले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा क्योंकि वृद्धि की वैधता संबंधी मुद्दे पर उच्च न्यायालय विचार कर रहा है।

आपरेटरों का कहना था कि एमसीडी को शुल्क बढ़ाने को अधिकार नहीं है।

तम्बाकू मुक्त दिल्ली के लिए परिसंवाद

नई दिल्ली। दिल्ली की स्वास्थ्य मंत्री प्रो. किरण वार्लिया का मानना है कि तम्बाकू उत्पादों पर दी जाने वाली सख्त वैधानिक चेतावनी और इसके दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक बनाने वाले विज्ञापन ज्यादा असर नहीं डालते हैं।

कांस्टीट्यूशन क्लब में मंगलवार को तम्बाकू मुक्त शहर दिल्ली-विषय पर आयोजित संविनार में एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने माना कि यूरोपीय देशों और अमेरिका में इन उत्पादों पर दी जाने वाली सख्त चेतावनी से लोगों के मन में ज्यादा डर पैदा होता है। वहां लोग इन उत्पादों के सेवन से डरते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में भी इस दिशा में काम हो रहा है। उन्होंने ऐसे उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की बजाय और सख्त कानून बनाने की जरूरत बताई। प्रो. वार्लिया ने गुटखे पर रोक लगाना सरकारी तंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। यह उत्पाद कानून के शिकंसे में ही नहीं आता। (प्र.सं.)

उसने 2000 फीसदी शुल्क बढ़ा दिया। एमसीडी ने 8 अप्रैल 10 को एक आदेश जारी कर मोबाइल टावरों को प्रति टावर एक लाख रुपये तथा एक लाख प्रति सर्विस प्रोवाइडर को देने का आदेश दिया था। इसके साथ ही यह शर्त भी जोड़ी थी कि इसके लिए उन्हें आरडब्ल्यू से भी अनुमति लेनी होगी साथ ही टावरों से निकलने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी ऊर्जा पर भी नियंत्रण रखना होगा।

आपरेटरों ने कहा कि उन्हें एयरपोर्ट अथॉरिटी, रेलवे, इसरो तथा नेवी से ही अनुमति लेनी की जरूरत होती है। एमसीडी इस मामले में कहीं नहीं है। एमसीडी एक्ट, 1957 की धारा 349 ए के तहत एमसीडी आयुक्त को केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत काम करना पड़ता है लेकिन इस मामले में केंद्र से कोई सलाह नहीं ली गई।

उन्होंने कहा कि एमसीडी का आदेश संविधान के अनुच्छेद 19(1) (जी), 21 तथा 14 मुक्त व्यापार करने के अधिकार का उल्लंघन है।

यदि नया शुल्क वसूलने की अनुमति दी गई तो आपरेटर उपभोक्ताओं

आंचल से ज्यादा जरूरी मां की गोद

कम वजन के जन्में बच्चों को मां की गोद में कहीं ज्यादा फायदा होता है

कार्यालय
नई दिल्ली

मां का आंचल नहीं बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए मां की गोद अधिक जरूरी है। कंगारू मदर केयर के जरिए जन्म के समय कम वजन के बच्चों को स्किन थैरेपी के जरिए नया जीवन दान दिया जा सकता है। देश में हर साल जन्म लेने वाले 2.5 करोड़ बच्चों में 1.5 करोड़ फीसदी बच्चे कम



अदालत का इंकार

- एमसीडी क्षेत्र दिल्ली में
- कुल टावर : 5500
- एमसीडी के अनुसार अवैध टावर : 2952
- पुराना शुल्क 100,000 रुपये
- नया शुल्क : 500,000 रुपये
- नए शुल्क के अनुसार कुल राशि : 55 करोड़ रुपये

को विश्व स्तरीय तथा सस्ती सेवा नहीं दे पाएंगे।

एमसीडी की बाछें खिली

नई दिल्ली। निगम अधिकारी और नेता दोनों ही इस बात से संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा और अब मोबाइल कंपनियों को फेसले के अनुसार तब राशि जमा करनी होगी। इससे प्रति टावर एक लाख रुपए की राशि तो निगम के खते में आएगी ही। साथ ही प्रति टावर एक लाख रुपए की एफडीआर भी जमा होगी। मालूम हो कि दिल्ली में करीब 5364 मोबाइल टावर हैं, इनमें से करीब 2412 टावर अनुमति के साथ लगाए गए हैं, जबकि 2952 अवैध टावर से लगाए गए हैं। दिल्ली नगर निगम ने कुछ समय पूर्व टावर लगाने की नई नीति बनाकर टावर लगाने का शुल्क पांच लाख रुपए कर दिया था। कंपनियों द्वारा शुल्क जमा नहीं करने पर निगम ने टावर सीलिंग शुरू की थी। विरोध में कंपनियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। अदालत ने सीलिंग पर रोक लगा दी थी। साथ ही एक लाख रुपए निगम के खते में तथा एक लाख रुपए की एफडीआर जमा करने के लिए कहा था। (प्र.सं.)

'दोस्ती की आड़ में बलात्कार के आरोपी को जमानत नहीं'

कार्यालय संवाददाता
नई दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने लड़कियों से दोस्ती कर बलात्कार करने के आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया है।

न्यायाधीश एस एन धींगरा ने पूर्वोत्तर की युवती की शिकायत पर दुष्कृत वर्मा के खिलाफ दर्ज किए बलात्कार के मामले में आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया। अदालत ने आरोपी के नौकरों के बयान के बजाय पर यह फैसला दिया। दो नौकरों ने निचली अदालत को बताया कि दुष्कृत अक्सर महिला मित्रों को घर लेकर आता था

दिल्ली में पिछले कुछ सालों से अकेले रह रहे दुष्कृत ने गत 18 अप्रैल को उसे अपने घर खाने पर बुलाया और जबरन उसके साथ यौन संबंध बनाए। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी पैसे वाले परिवार से ताल्लुक रखता है और दिल्ली में पिता के पैसे से पूरे टाट बाट से रह रहा है।

In Loving Memory of Our Beloved Father Late Shri M.K. Bhambrī (Sinha) (10.10.1934 - 23.06.2001)
 Who left us on this day Nine years ago. Deeply missed & remembered by Sarjat Bhambrī (Goldy) & Family.

In Loving Memory of MRS. GEETU ARORA 11.05.1977 - 23.06.2008
 Truth is no one dies our limited capability makes us think so. I am holding to this truth my wife of all birth U R alive for me Geetu & will remain so. Luv U

1st Death Anniversary VIJAY KUMAR GUPTA Ex-CMD, NEPA Ltd. 04.11.1941 - 23.06.2009
 Those we love don't go away. They walk beside us every day. Unseen, unheard, but always near. Still loved, still missed and very dear. Kamini, Ashwani, Sonal, Ram & Om Geetanjali. Shashi, Gayatri & Shiv. Tel: 9810631424, 9312658327, J-54 Saket, New Delhi-17. M/S Delhi Paper & Allied Agencies, Hotel Rama Inn, M/S A.K. Enterprises.